विश्व के दुर्लभतम जानवरों में से एक हैं चिलिंघम के जंगली वाइट कैटल। दूर से देखने पर तो ये बेहद शांत और आकर्षक नज़र आते हैं, लेकिन, घिर जाने पर बहुत आक्रामक तरीके से ये अपना बचाव करते हैं। चिलिंघम का यह वाइट कैटल झुण्ड उत्तरी नॉर्थम्बरलैंड में 150 हैक्टेयर क्षेत्र में रहता है और उन जानवरों के वंश का है जो प्राचीन काल में ब्रिटेन के जंगलों में विचरता था। लेकिन, इस समय पाण्डा से भी अधिक दुर्लभ है। इस वर्ष यहाँ लगभग 130 मवेशी ही हैं। इसलिए इन्हें माउण्टेन गोरिल्ला और पांडा से भी ज्यादा दुर्लभ कहा जा सकता है। इन मवेशियों को पालतू नहीं बनाया जा सकता है। ये जंगली जानवरों की तरह रहते हैं, ना कोई इनकी देखभाल करता है ना कोई पशु चिकित्सक इनका उपचार करता है। लेकिन 700 साल पहले नॉर्थम्बरलैण्ड के डिअर पार्क में इन्हें क्यों लाया गया था, यह अभी तक पता नहीं चला है। पार्क की वॉर्डन एली वैडिंगटन का कहना है, ''ये वाइल्ड कैटल विश्व के ऐसे जीवों में से एक हैं, जिनका सबसे ज्यादा अन्तः प्रजनन हुआ है। सदियों से इनके साथ किसी भी तरह का कोई इंसानी दखल नहीं रहा है और ना ही अन्य मवेशियों की तरह इनके लिए किसी तरह की बेहतर प्रजनन प्रक्रिया अपनाई गई है।'' एली कहती हैं कि ''अविश्वसनीय रुप से, अंतः प्रजनन के बावजूद ये अभी तक मौजूद हैं, यह एक चमत्कार ही है। जबकि, लंबे समय तक अंतः प्रजनन के परिणामस्वरुप जानवरों की प्रजनन क्षमता खत्म हो जाती हैं और वो मर जाते हैं।'' ये मवेशी छोटे-छोटे उपसमूहों में रहते हैं। हरेक का मुखिया एक बैल होता है। जब युवा बैल मुखिया को चुनौती देता है तो भारी लड़ाई होती है और यदा -कदा इसमें एक की मौत हो जाती है, क्योंकि ये बहुत जिद्दी जानवर हैं और पीछे नहीं हटते। पहली बार मां बन रही मादा बेहद उग्र होती है और वो भी आक्रामक होकर हमला कर सकती है। इन दुर्लभ जानवरों को डियर पार्क का प्रबंधन करने वाली संस्था द्वारा आयोजित टूर्स के माध्यम से ही देखा जा सकता है।

‘क्या पृथ्वीराज नगर में बिजली कनैक्शन देने में भेदभाव बरता गया है?’

हाई कोर्ट ने इस प्रश्न को उठाने वाली सभी याचिकाओं की सुनवायी करने के लिये मन बनाया

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 22 मई । राजस्थान हाईकोर्ट में पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में बिजली कनेक्शन आवंटित नहीं किये जाने या भेदभाव करते हुए बिजली कनेक्शन आवंटित किये जाने से संबंधित कई याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई होगी। इस मामले में न्यायाधीश समीर जैन ने सभी संबंधित मामलों को संगठित तौर पर सुनने के लिये सूचीबद्ध किया है। अदालत ने अधिवक्ता पी.एन. भंडारी, जो ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं और ‘राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड’ (आर.एस.ई.बी.) के अध्यक्ष भी रहे हैं, को न्याय मित्र घोषित किया है।

- **यह मामला, पृथ्वीराज नगर में 10 हजार विवादास्पद बिजली कनेक्शन देने के मसले से जुड़ा है।**
- **जे.डी.ए. ने पूर्व में बिजली कनैक्शन देने का भारी विरोध किया था, क्योंकि लोग बिजली कनैक्शन के आधार पर भूखंडों का नियमन करवा रहे थे।**
- **पर, डिस्कॉम ने कनैक्शन देने के पक्ष में यह तर्क दिया है कि, काफी समय से पृथ्वीराज नगर में बिजली कनैक्शन नहीं जारी होने के कारण, बिजली की भारी चोरी हो रही है।**
- **न्यायालय ने अधिवक्ता पी.एन. भण्डारी को न्याय मित्र घोषित किया है। भण्डारी, आर.एस.ई.बी. के अध्यक्ष भी रहे हैं तथा ऊर्जा विशेषज्ञ हैं।**

राजस्थान हाईकोर्ट ने करीब 10 वर्ष पूर्व आदेश पारित किये थे कि पृथ्वीराजनगर क्षेत्र में नये बिजली कनेक्शन नहीं दिये जायें क्योंकि कई लोग जिनके पास जे.डी.ए. द्वारा आवंटित पट्टे नहीं थे, वे बिजली कनेक्शन आवंटित कराकर, मौके का कब्जा दर्शाकर अपने भूखंडों को नियमितकरण करा लेते थे। जे.डी.ए. द्वारा इस तरह की कार्रवाई का भारी विरोध किया जाता था क्योंकि पट्टे आवंटन का सही मूल्य नहीं मिलने पर उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता था।

परंतु 2016 में डिस्कॉम की ओर से अदालत में यह बताते हुए अर्जी पेश की कि पृथ्वीराज नगर में बिजली की भारी चोरी की जा रही थी और उसे रोकने के लिये नये बिजली कनेक्शन आवंटित किया जाना ही व्यवहारिक हल है। इस मामले को जानने वाले सूत्रों ने बताया कि जे.डी.ए. ने डिस्कॉम द्वारा दी गई अर्ज़ी का भारी विरोध किया था, जिसके चलते डिस्कॉम्स को अपनी अर्जी वापस लेनी पड़ी थी।

सूत्रों का कहना है कि यह मामला उक्त क्षेत्र में करीब 10000 बिजली कनेक्शन आवंटित करने से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि ‘इलेक्ट्रिसिटी एक्ट’ के तहत बिजली कनेक्शन भूखंड के मालिक को ही नहीं बल्कि किरायेदार के नाम या भूखंड पर कब्जा करने वाले के नाम भी दिया जा सकता है। अदालत ने इस तथ्य को नजर में रखते हुए बिजली कनेक्शन आवंटित किये जाने के संबंध में इन मामलों पर सुनवाई करना शुरू किया है। इन्हीं मामलों से संबंधित कुछ अन्य मामलों में अदालत ने अधिवक्ता महेन्द्र शांडिल्य को न्याय मित्र भी घोषित किया है।

मेहम चौबीसी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा आई.पी.सी. की अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। दूसरा केस वयस्क महिला पहलवानों द्वार लगाए गए आरोपों से संबंधित है।

पदक विजेता विनेश फोगाट, जो प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं, ने सिहं की नार्को टैस्ट करवाने की चुनौती स्वीकार कर ली है। सिंह ने कहा था कि वे नार्को टैस्ट, पॉलिग्राफ टैस्ट, लाइ डिटैक्टर टैस्ट करवाने को तैयार हैं, बशर्ते कि विनेश फोगाट व बजरंग पूनिया भी टैस्ट करवाएं। विनेश ने एक प्रैस कॉन्फ्रैंस में कहा कि, मैं बृजभूषण से कहना चाहती हूं कि न केवल विनेश वरन् वे सभी लड़कियां जिन्होंने शिकायत की है, नार्को टैस्ट करवाने को तैयार हैं। टैस्ट लाइव होना चाहिए ताकि पूरे देश को पता लगे कि देश की बेटियों के साथ उसका व्यवहार कितना क्रूर है।

कांग्रेस मानसून सत्र में केन्द्रीय सरकार के नये दिल्ली अध्यादेश का कड़ा विरोध करेगी

केन्द्र सरकार के खिलाफ लड़ाई में केजरीवाल को कांग्रेस का साथ मिलने से लोग विस्मित से हैं

नई दिल्ली, 22 मई। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कहा है कि जुलाई में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के कार्यकारी आदेश का विरोध करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने आज शाम संवाददाताओं से कहा, ''कांग्रेस संसद में जारी दिल्ली अध्यादेश का विरोध करेगी।''

- **कांग्रेस ने कहा है कि, पार्टी संसद के मानसून सत्र में, दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों पर केंद्र के अध्यादेश का कड़ा विरोध करेगी।**

पिछले शुक्रवार देर शाम केंद्र की मोदी सरकार ने एक अध्यादेश लाया था, जो सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले और आदेश को रद्द करता है, जिसमें कहा गया था कि चुनी हुई सरकार दिल्ली की बॉस है और अधिकारियों के तबादले पर राज्य सरकार का कंट्रोल रहेगा। इस फैसले के सात दिन बाद केंद्रे सरकार ने अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि तबादले का अधिकार उप राज्यपाल के पास ही रहेगा।

गौरतलब है कि, आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले सभी विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर सहयोग मांगा था। केजरीवाल ने कहा था कि अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो 2024 में बीजेपी को हराने में मदद मिल सकती है। एक दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केजरीवाल से मुलाकात की थी और इस मुद्दे पर संसद में साथ देने का भरोसा जताया था।

दरअसल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अच्छे संबंध नहीं रहे लेकिन विपक्षी एकता और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की मुहिम को धार देने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है।

फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया

नई दिल्ली/पोर्ट मोरेस्ब 22 मई (वार्ता)। फिजी ओ पापुआ न्यू गिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने-अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। फिजी के प्रधान मंत्री सित्विनी राबुका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को फिजी के सर्वोच्च सम्मान- ‘द कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी (सी.एफ.)’ से सम्मानित किया। वहीं मोदी को पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ग्रैंड कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू (जी.सी.एल.) से नवाजा गया। पोर्ट मोरेस्बी, पापुआ न्यू गिनी में तीसरे एफ.आई.पी.आई.सी. शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार स्वीकार करते हुए धन्यवाद व्यक्त किया।

‘एक हजार के नोट फिर से नहीं चलेंगे’

आर.बी.आई. ने एक हजार रुपये मूल्य का नोट फिर से चलन में लाए जाने की चर्चाओं को अटकलबाजी बताया

मुंबई, 22 मई (वार्ता)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक हजार रुपये मूल्य का नोट फिर चलन में फिर लाए जाने की चर्चाओं को अटकलबाजी बताया है, साथ ही यह भी कहा कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं होगा।

- **आर.बी.आई. गवर्नर ने 2000 रुपये का नोट वापस लेने के कदम को केंद्रीय बैंक की मुद्राप्रबंधन व्यवस्था के तहत की गयी एक कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि, इस निर्णय के बाद कितने नोट वापस आएंगे, यह समयावधि खत्म होने के बाद ही सही-सही पता लगेगा।**

आर.बी.आई. गवर्नर ने यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में एक हजार रुपये का नोट फिर शुरू करने के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि यह अटकलबाजी है। उन्होंने कहा, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आर.बी.आई. की स्वच्छ बैंक नोट नीति के तहत दो हजार रुपये का नोट वापस लेने की घोषणा के बाद से कुछ हलकों में चर्चा है कि केंद्रीय बैंक 1000 रुपये का नोट फिर चलन में लाया जा सकता है। हजार रुपये का नोट आठ नवंबर 2016 को घोषित नोटबंदी में चलन से बाहर कर दिया गया था। उसी समय 2000 का नया नोट चलन में आया था। इसे अब लोग 23 मई 2023 से बैंकों के माध्यम से बदलवा या खातों में जमा करा सकते हैं।

दास ने 2000 रुपये का नोट वापस लेने के कदम को केंद्रीय बैंक की मुद्राप्रबंधन व्यवस्था के तहत की गयी एक कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद कितने नोट वापस आएंगे, यह समयावधि खत्म होने के बाद ही सही-सही पता लगेगा।

‘नई संसद के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को हैरानी जताई कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को रविवार को हो रहे नए संसद भवन के उद्घाटन का निमंत्रण तक नहीं भेजा गया है। मोदी रविवार को नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं

एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए खड़गे ने कहा, संसद भारतीय गणतंत्र की सर्वोच्च विधायी इकाई है और राष्ट्रपति देश की सर्वोच्च संवैधानिक ''अथॉरिटी'' हैं। वे सरकार, विपक्ष व सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन से लोकतांत्रिक मूल्यों व संविधान के प्रति सरकार को प्रतिबद्धता का संकेत मिलेगा। लोकसभा स्पीकर ने राष्ट्रपति से आग्रह करने की बजाय प्रधानमंत्री को नई ससंद के उद्घाटन का निमंत्रण दिया।

मणिपुर में फिर हिंसा भड़की, आगजनी के बाद सेना ने फिर से मोर्चा संभाला

हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस ने भाजपा के तीन पूर्व विधायकों को गिरफ्तार किया

इंफाल, 22 मई। मणिपुर के पूर्वी इंफाल जिले में हथियार बंद दो बदमाशों ने सोमवार को लोगों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया, जिसके बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। उग्र भीड़ ने दो घरों में आग लगा दी। हालांकि, आगजनी की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।

- **मणिपुर के पूर्वी इम्फाल जिले में दो हथियारबंद बदमाशों ने सोमवार को लोगों को अपनी दुकानें बंद करने के लिए बाध्य किया, जिसके बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी।**
- **इसके बाद उग्र भीड़ ने दो घरों में आग लगा दी और देखते ही देखते बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर उतर आये और जगह-जगह टायर इत्यादि जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे।**

भीड़ ने एक बदमाश की पिटाई भी की, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। दोनों को हिरासत में ले लिया है। क्षेत्र में तैनात सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे जिससे कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं।

स्थानीय लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर इस घटना का विरोध किया। पूर्वी इंफाल जिले में पहले कर्फ्यू में ढील दी गई थी लेकिन इस घटना के बाद आज फिर से उसे कड़ा कर दिया गया। इलाके में इंटरनेट सेवा पहले से ही सस्पेंडेड है।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घटनाक्रम की पुष्टि की है और जोर देकर कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हिंसा में कथित संलिप्तता के आरोप में सोमवार को बीजेपी के एक पूर्व विधायक समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूर्व विधायक की पहचान चुराचांदपुर जिले के हेंगलेप निर्वाचन क्षेत्र के टी थंगजालम हाओकिप के रूप में हुई है।

1.8 करोड़ लोगों ने किया कश्मीर भ्रमण

श्रीनगर, 22 मई (वार्ता)। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने रविवार को कहा कि वर्ष 2022 के दौरान रिकॉर्ड एक करोड़ 80 लाख से अधिक पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया। जी 20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले रविवार को एस.के.आई.सी.सी. में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मेहता ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले एक साल में सबसे ज्यादा संख्या में पर्यटकों के आने से जमीनी स्तर पर बदलाव आया है। मेहता ने कहा कि पर्यटकों की आमद को देखते हुए जम्मू-कश्मीर में 300 नए पर्यटन स्थल खुलेंगे और प्रत्येक गंतव्य पर्यटकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में सबसे अधिक संख्या में विदेशी पर्यटकों का आना जम्मू-कश्मीर में पर्यटन के लिए एक स्वस्थ संकेत है।

कोटखावदा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण सड़कों पर उतर आए और शवों को कोटखावदा बस स्टैंड पर रखकर परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बाजार बंद करवा दिया और जाम लगा दिया।

गत शाम सांसद किरोड़ी लाल मीणा परिजनों के पास पहुंच उन्हें ढांढस बंधाया। स्थानीय विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के नहीं आने से लोगों में भारी नाराजगी देखी गई। सोमवार को करीब 12.30 बजे सचिन पायलट परिजनों से मिलने आए उनके साथ वेद सोलंकी भी थे। ग्रामीणों ने वेद सोलंकी के प्रति नाराजगी जाहिर की व उनका भारी विरोध किया। पायलट करीब 20 मिनट तक परिजनों के साथ रहे और उन्हें सांत्वना दी तथा ग्रामीणों से भी वार्ता की।

माहौल की गंभीरता को देखते हुए मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तीन थानों का पुलिस जाप्ता तैनात है।

जानकारी के मुताबिक रविवार शाम सांसद मीणा के पहुंचने पर मृतक के परिजनों सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के बीच सीएचसी में हुई बैठक मे सहमति बनी। चारों मृतकों को कुल 53 लाख रुपए ही सहायता राशि, दोनों घायलों को 4-4 लाख रु. देने पर परिजनों के साथ सहमति बनी है। धरना समाप्त करने की घोषणा के बाद मौके से शवों को उठाकर दाह संस्कार के लिए ले जाया गया।

इस दौरान डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने अपने वेतन से नगद 2 लाख रु. की राशि मृतकों के परिजनों को सौंपी। सोमवार को विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने भी चिरंजीवी योजनाओ से परिजनों को 10 लाख रु. की सहायता राशि का चैक सौंपा अपना 2 महीने का वेतन भी पीड़ित पक्ष को देने की घोषणा की।

खड़गे ने चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राज्य अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दल के नेता, विधानसभाध्यक्ष और कुछ चयनित नेता मीटिंग में शामिल होंगे। इस मीटिंग में राहुल गांधी और ए.आई.सी.सी. पदाधिकारी भी भाग लेंगे।

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार तथा छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पहले ही कई समाज कल्याण योजनाओं की घोषणा कर चुकी हैं। कर्नाटक में पार्टी की ''पांच गारंटियों'' को वहां के मतदाताओं की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी उसके संदर्भ में इन जन कल्याण योजनाओं की मीटिंग में समीक्षा की जाएगी।

कर्नाटक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, ''मैं नहीं मानता कि सरकार को 3.1 लाख करोड़ के आकार वाले कर्नाटक-बजट से (इन पाँच गारन्टियों के लिये) 50,000 करोड़ रू. प्रति वर्ष जुटाना असंभव होगा।''

दृढ़निश्चयी नज़र आ रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि जब राज्य 56,000 करोड़ रू. वार्षिक ब्याज-भार वहन कर रहा है तो क्या जनता के लिये 50,000 करोड़ रू. खर्च नहीं कर सकता।

नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह का विपक्ष...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रतिक्रिया देते हुये, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुये, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नये संसद भवन का उद्घाटन किये जाने पर राहुल गांधी की आपत्ति को ''बाल हठ'' की संज्ञा दी।

भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, ''ऐसा क्यों होता है? जब देश प्रगति कर रहा है, ऐसी शुभ समयावधि के दौरान वे एक अपशकुन की तरह सामने आ रहे हैं। उनकी सोच इतनी छोटी है कि वे एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण का स्वागत-अभिनंदन नहीं कर पा रहे, जिस क्षण नया संसद भवन लोकतंत्र के मंदिर का रूप ले रहा होगा।''

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि वह नये संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रपति तथा पूर्व राष्ट्रपति को आमंत्रित न करके, ''बार-बार मर्यादा का उल्लंघन कर रही है।'' उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा-आर.एस.एस. सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रपति पद केवल एक ''प्रतीक'' के रूप में सिमटकर रह गया है।

खड़गे ने ट्वीट श्रृंखला में लिखा, ''ऐसा प्रतीत होता है, मानो मोदी सरकार ने भाजप के राष्ट्रपति का चुनाव दलित एवं आदिवासी समुदायों से करना केवल चुनावी कारणों से सुनिश्चित किया है।''

उधर भाजपा नेता भाटिया ने कहा कि कांग्रेस नेता तथा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि हमें एक नये संसद भवन की जरूरत है। कांग्रेस को ''निरर्थक'' बताते हुए, भाटिया ने कहा कि उसे (कांग्रेस) को इस बात में परेशानी है कि प्रधानमंत्री मोदी उनके (कांग्रेस) के सपने को साकार कर रहे हैं।

भाटिया ने कहा, '' (वरिष्ठ कांग्रेस नेता) जयराम रमेश ने यही बात कही थी। इसका स्वप्न देखने वाले वही (कांग्रेस) थे, इसके बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गये तथा अपने-सपने को साकार नहीं कर सके, वे इतने बेकार हैं और जब प्रधानमंत्री मोदी उनके सपनों को आकार दे रहे हैं तथा चूंकि यह देश-हित में भी हैं, इसलिये उन्होंने छाती-पीटना शुरू कर दिया है।''

मल्लिाकुर्जन खड़गे ने आरोप लगाया कि, जहां पूर्व राष्ट्रपति नये संसद भवन के शिलान्यास समारोह में आमंत्रित नहीं किये गये थे, वहीं वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नये संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं की जा रही हैं।

खड़गे ने ट्वीट किया है, ''भारत की संसद भारतीय गणतंत्र की सर्वोच्च विधायी संस्था है तथा भारत के राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी हैं। वे सरकार, विपक्ष तथा प्रत्येक नागरिक का समान रूप से प्रतिनिधित्व करती हैं। वे भारत की प्रथम नागरिक हैं। उनके द्वारा नये संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों तथा संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीत होगा।''

नये संसद भवन की उद्घाटन तिथि, 28 मई के दिन ही हिंदुत्ववादी वी.डी. सावरकर की जयंती भी है तथा इस बात को लेकर भी बहुत से विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस, इसे देश की बुनियाद रखने वाले पूर्वजों का ''घोर अपमान'' कहा है। इस टिप्पणी पर एतराज करते हुये, गौरव भाटिया ने कहा कि उद्घाटन की तिथि पर सवाल खड़े करने वाले लोग ''महत्वहीन एवं असंगत'' हैं।

उन्होंने कहा, ''वीर सावरकर हर भारतीय का गौरव है। (उद्घाटन) तिथि पर सवाल खड़े करने वाले लोग बता रहे हैं कि अप्रासंगिक हैं तथा वीर सावरकर के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है।''

कई विपक्षी नेताओं ने प्रश्न खड़ा किया है कि नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के बजाय प्रधानमंत्री मोदी क्यों कर रहे हैं। आर.जे.डी. नेता मनोज कुमार झा, सी.पी.आई. नेता डी. राजा तथा ए.आई.एम.आई.एम. प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर अत्यन्त कटु टिप्पणी करते हुये केन्द्र सरकार पर प्रहार किया है।

डी. राजा ने कहा है, ''जहां तक मोदी जी की बात है, अपनी छवि की सनक तथा कैमरे (के सामने रहने की लालसा) ने मर्यादा एवं मानदंडों को समाप्त कर दिया है।''

ओवैसी ने कहा, ''वे (मोदी) कार्यपालिका के मुखिया हैं, व्यवस्थापिका के नहीं। हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति (इसका) उद्घाटन कर सकते थे। यह जनता के पैसे से बना है, प्रधानमंत्री ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, मानो उनके ''मित्रों'' ने अपने निजी पैसे से इसका खर्च उठाया हो।''

लोकसभा सचिवालय में 888 सदस्य तथा राज्यसभा चैम्बर में 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं।

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की स्थिति में, लोकसभा चैम्बर में 1,280 सदस्य समायोजित हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने नये संसद भवन की आधारशिला 10 दिसम्बर 2020 को रखी थी।

डेढ़ माह ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की तिथि पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल तथा जे.डी. (यू) अध्यक्ष लल्लन सिंह भी मीटिंग में उपस्थित थे। इससे एक दिन पूर्व कुमार तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भाजपा से टक्कर लेने के लिये विपक्षी एकता की जरूरत बताई थी।

उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, एन.सी.पी. अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडू के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तथा नैशनल कॉन्फ्रैंस के अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठे हुये थे ताकि विपक्ष की एकता का प्रदर्शन हो सके। एकता, जो अभी ठोस रूप नहीं ले पाई है, की कवायद के लिये नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं तथा क्षेत्रीय छत्रपों के साथ मीटिंगों का सिलसिला जारी रखे हुये हैं।

कर्नाटक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा रही हैं, जिनमें विधानसभा चुनाव तथा लोकसभा चुनाव जीतने पर चर्चा की जा रही है।

गत दिनों मध्य प्रदेश इकाई की बैठक हुई और रविवार को राजस्थान और बिहार इकाई की बैठक हुई जिसका लक्ष्य मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा करना था, ये कार्यक्रम एक माह तक चलेंगे, पर मुख्य फोकस कर्नाटक की हार के संदर्भ में आगामी विधानसभा चुनावों पर केन्द्रित रहा।

19 मई को मध्य प्रदेश के सभी नेताओं की भोपाल में बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। उन्होंने कहा कि ''हमें कर्नाटक की हार से निराश होने की जरुरत नहीं है। क्योंकि वहां कांग्रेस को जनता दल (एस) का वोट शेयर मिला इसलिए वह जीती, यहां कोई तीसरी पार्टी नहीं है, मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच है।''

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोनः 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908